





# प्रयागराज संदेश

## खबर संक्षेप

10 लाख रंगदारी मांगने में अतीक के शूटर तोता समेत पांच नामजद

प्रयागराज। अतीक आहंक के शूटर जुलिकरार उफ तोता तोता समेत पांच पर धूमनारंग थाने में 10 लाख रंगदारी मांगने में बुकदामा दर्ज किया गया है।

प्रॉपर्टी डॉलर मो. परवेज का आरोप है कि तोता का नाम लेकर चार गुणों ने उससे रंगदारी मांगी। दो धारा कार

50 हजार रुपये भी ले लिए थे। किया गया है।

कस्तरी मसारी निवासी परवेज ने पुलिस को बताया कि 25 अप्रैल को वह अपनी बहन के घर गया था। तात आठ बजे आते वक्त रास्ते में अकरम, अपने भाई अमरज, असलम निवासी अहमदपुर असलमी हालपता चकिया कसरी मसारी व फैजान ने उसे रोककर गालीलोज शुल्क कर दी। दो धारा कार

एकरम व फैजान ने कहा कि उन्हें यहां है और उपर्युक्त तोता समेत पांच पर धूमनारंग थाने में 10 लाख रंगदारी मांगने में बुकदामा दर्ज किया गया है।

प्रॉपर्टी डॉलर मो. परवेज ने बुकदामा दर्ज किया गया है।







# संपादकीय

# गांधी और गांधीवाद पर<sup>1</sup> हमला सुनियोजित साजिश

गांधीवादी डॉ. सुदर्शन अयंगर ने लगभग एक दशक पहले प्रकाशित एक पेपर में लिखा था- 'कई (गांधीवादी) संस्थान संकट में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बुनियाद कमज़ोर हो गई है जो विचार की गरिबी और व्यवहार में कठारता दोनों को दर्शाती है। प्रतिबद्ध व्यक्तियों की संख्या कम है। सामान्य तौर पर मामूली सामाजिक सेवा को छोड़कर, गांधीवादी विचारों और कार्यों के लिए व्यापक सामाजिक समर्थन लगभग न के बराबर है।' गांधीवादी विचार, संस्थान और स्वयं महात्मा गांधी पर आज अभूतपूर्व हमले हो रहे हैं। सरकार में शामिल लोगों से लेकर कार्यकर्ताओं तक अपने जहरबुझे दिमाग से गांधी और उनके विचारों पर लगातार हमले कर रहे हैं। राष्ट्रपिता को गलत और यहां तक कि खलनायक बताने की कोशिशें की जा रही हैं। इन घटनाओं से गांधीवादी हैरान हैं, लेकिन हमलों की उग्रता और मैदिया चैनलों पर फैलाए जा रहे जहर के कारण उनके मन में मायूसी, हार और इस विवाद में शामिल न होने की भावना भी है। इन परिस्थितियों में गांधीवादियों को क्या करना चाहिए? उन्हें कैसे जबाब देना चाहिए? विडंबना यह है कि 2 फरवरी, 1948 को वर्धा में आयोजित होने वाले एक सम्मेलन में चर्चा के केंद्र में ये सवाल थे। हालांकि उस समय संदर्भ अलग था- स्वतंत्रता के बाद के भारत को मजबूत करने के लिए प्रयास। उस सम्मेलन से तीन दिन पहले ही गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसलिए इस सम्मेलन का बाद में मार्च में आयोजन करना तय किया गया। इसका विषय था- 'गांधी चले गए। अब हमें क्या करना चाहिए?' (गांधी इज गॉन, व्हॉट शुड वी डू नॉउ?) 13-15 मार्च, 1948 को हुए उस सम्मेलन में सर्व सेवा संघ की स्थापना की गई इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने की थी और इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, आचार्य जेबी कुपलानी, जेसी कुमारपण, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे जैसे लोगों ने 'सच्चेदिल, आत्म-अलोचना और निष्पक्षता के साथ अपनी बातें रखीं, जिसने अपने शहीद मार्गदर्शकों को भी छूट नहीं दी। इस विचार मंथन को 'गांधी इज गॉन, डू विल गाईड अस नॉउ?' (संपादक गोपालकृष्ण गांधी, परमानेंट ब्लैक द्वारा प्रकाशित) में छापा गया। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभभाई पटेल भी शामिल होने वाले थे।

थलाकन खराब स्वास्थ्य के कारण व नहीं आ सक। यह तय किया गया कि सर्व सेवा संघ दलगत राजनीति से दूर रहकर इस उद्देश्य से काम करेगा कि-'मानव और लोकतात्रिक मूल्यों से ओत-प्रोत सत्प्राणी और अहिंसा पर आधारित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की शुरूआत की जा सके जो शोषण, अत्याचार, अनैतिकता या अन्याय से मुक्त हो और जो मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे।' इस समय सर्व सेवा संघ और वाराणसी में उसके द्वारा संचालित संस्थाएं, स्थानीय प्रशासन और रेलवे के खिलाफ उच्च न्यायालय में उस नोटिस के खिलाफ लड़ रही हैं जो दावा करते हैं कि जिस भूमि सरकार से विधिवत खरीदी गई थी। संपत्ति गिराने को नोटिस और वास्तविक तोड़फोड़ के लिए तय की गई तरीखें बिजली की गति के साथ आई हैं और सरकारी मशीनरी काम करने के अपने ढीले-ढाले तरीके के एकदम विपरीत है। इस मामले पर प्रकाश डालते हुए एक सदस्य ने कहा कि -'गांधीवादी संगठन आज दुर्दशा और खतरे का समान कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि 'वाराणसी में सर्व सेवा संघ पर हमला हो रहा है। हम इसे बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।' अगर सर्वसेवा संघ के समृद्ध इतिहास, इसके इरादे की शुद्धता (सार्वजनिक जीवन में सच्चाई) और इस संगठन को बनाने वाले नेताओं के नाम भी सरकारी अधिकारियों को सर्व सेवा संघ की इमारतों को ध्वस्त करने से नहीं रोक सके तो गांधीवादी आंदोलन के बचे हुए लोगों में से लगभग किसी को भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इसमें कोई सदैह नहीं है कि गांधी विरोध की यह दिशा घृणित है। इसका विरोध करने के लिए हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिए। हमारे भीतर के सर्वेष्ठ कानूनों को पोषण करने वाली गहरी, समृद्ध और विकसित सोच जो हमारी विरासत और लोकाचार की बात करती है, उसे एक ऐसे स्तर पर लाया जा रहा है जो गांधी के कद को कम करता है। सही सोच वाले सभी भारतीयों को इन हरकतों से चिर्तित होना चाहिए। फिर भी, गांधी विरोधी सोच हर तरह से फल-फल रही है। 1948 में उठाया गया सवाल 2023 में फिर हमारे सामने खड़ा है; फर्क सिफ्फ इतना है कि अब 'हमारी सरकार पर खुली शुत्रा, वैमनस्य को बढ़ावा देने और गांधीवादी सोच की जड़ों पर प्रहार करने वाले विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है। फिर भी, आजादी की 75 साल की यात्रा में इस सवाल की समानता हमें एक व्यक्ति के रूप में और गांधीवादी आंदोलन के बारे में बहुत कुछ बताती है। दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम उन शक्तियों को दोष दे सकते हैं और उन्हें दोष देना भी चाहिए जो इसका कहानी को आकार देते हैं कि गांधी हमारे असली नायक नहीं हैं और इस विचार को बेचने के लिए अंतहीन घंटों के एयर टाइम और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, परन्तु वे इस कथा को इतनी सफलतापूर्वक ले जा रहे हैं कि हमें बताते हैं कि गांधी के आदर्श वास्तव में भारतीयों के दिल और दिमाग में अंतर्निहित नहीं हैं। इसलिए यह दोष उन सभी लोगों द्वारा भी साझा किया जाना चाहिए जिन्हें गांधीवादी के रूप में जाना जाता है।

**इंटरनेट की शक्ति का जश्न - डिजिटल इंडिया का इंटरनेट उत्सव**

किशन भावनाना गाद्या

हानि है, जिसमें हमारा पाइए से लकर अमेरिकन राष्ट्रपति, एशिया और यूरोपीयन स्ट्रेटस से लेकर नाटो तक वर्चुअल सभाएं होती है। चूंकि शुक्रवार दिनांक 7 जुलाई 2023 को भारत में इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए भारत इंटरनेट उत्सव लांच किया गया है, इसलिए आज हम मीडिया और पीआईबी में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्ञान को साझा करने के एक अनिवार्य उपकरण के रूप में उभरा है, नागरिकों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट सुनिश्चित करने को खोखांकित करना जरूरी है। साथियों बात अगर हम इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनानेडिजिटल भारत का इंटरनेट उत्सव मनाने की करें तोइंटरनेट की परिवर्तनकारी भूमिका को अपनाने के लिए ढीओटी मायगोव के सहयोग से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहें हैं, जिसमें नागरिक किसी भी सोशल मीडिया

कर सकत है नियंत्रण को कैसे बदल दिया है।  
या ड्राइव लिंक में अपलोड लिंक को मायगोव पर सकता है। सर्वश्रेष्ठ कहा रुपये तक के पुरस्कार दिमायगोव पर 07  
21.08.2023 तक आ डीओटी त्वरित समावेशी विकास के लिए कभी भी विश्वसनीय, सस्ती और एकीकृत दूरसंचार सेवाएं लिए लगातार काम करनेविटी, ज्ञान को सामाजिक आर्थिक विवराय उपकरण के दूरसंचार विभाग (डीओटी) सर्विस ऑफिस गोनां फंड माध्यम से देश के विभिन्न दरदराज और व्याव

न लागा के जावन  
रत इंटरनेट उत्सव  
ड करें, और उसी  
सबमिट किया जा  
नयों को 15,000  
जाएं प्रतियोगिता  
07.2023 से  
प्रोजित की जाएगी।  
सामाजिक आर्थिक  
कहीं भी सुरक्षित,  
उच्च गुणवत्ता वाली  
सुनिश्चित करने के  
रहा है। इंटरनेट  
सज्जा करने और  
सास के लिए एक  
रूप में उभरा है।  
(टी) नेयूनिवर्सल  
(यूएसओएफ) के  
हिस्सों विशेषकर  
आयिक रूप से

इतरन  
उठाए  
यात्मक,  
ए गए  
हुआ।  
क साइट  
अधिक  
त दुनिया  
त्रों में से  
  
पम करने  
ग 10  
मानवीय  
र सशक्त  
डिजिटल  
तीव्रता में  
हो सकें।  
टरेन ने  
देश के  
जीवन

# आर्थिक लोकायुक्त से इतना डर क्यों ?

जयसिंह रावत



शासक भी आते हैं, इसलिये संभवतः लोकायुक्त का गठन में संकोच होता है। अभी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कराना या न कराना शासन-प्रशासन के हाथ में है लेकिन लोकायुक्त व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सीधे लोकायुक्त से किसी के भी खिलाफ जांच की मांग कर सकता है। लोकपाल का डर ही था कि 1968 से लेकर 2013 तक संसद लोकपाल का कानून पास नहीं कर सकी। लोकपाल कानून बनने के 5 साल बाद केन्द्र में पिनाकी चन्द्र घोष को लोकपाल के तौर पर नियुक्त हो सकी मगर उनका कार्यकाल 27 मई 2022 को पूर्ण होने के बाद भी नये लोकपाल की नियुक्ति के बिना केन्द्र में प्रभारी लोकपाल से काम चलाया जा रहा है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशल इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संसद द्वारा पारित लोकपाल-लोकायुक्त कानून के अस्तित्व में आने के बाद भी 28 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में से 9 ने अभी तक केन्द्रीय

कानून के अनुरूप या समरूप अपने लोकायुक्त कानून में संशोधन नहीं किया। देश के 28 राज्यों के साथ ही 3 केन्द्र शासित प्रदेशों से जुटाये गये इन आंकड़ों के अनुसार 8 ने लोकायुक्त का गठन नहीं किया। इन राज्यों में उत्तराखण्ड, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पुडुचेरी हैं। जम्म-कश्मीर में जो संस्था थी वह भंग है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद भी उत्तराखण्ड जैसे कुछ राज्यों ने लोकायुक्त के गठन की पहल नहीं की। सन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 राज्यों के मुख्य सचिवों को अपने यहां यथाशीघ्र लोकायुक्तों के गठन के निर्देश दिये थे। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशल की रिपोर्ट के अनुसार 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी आवश्यक उपलोकायुक्तों (सदस्य) की नियुक्ति नहीं हुई। आज एक देश एक कानून की बात तो होती है मगर लोकायुक्त कानूनों में एक

रुपता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जहां शिकायत दर्ज करने का शुल्क मात्र 3 रुपये है वहीं गुजरात और उत्तर प्रदेश में यह शुल्क 2000 रुपये रखा गया है।  
कुछ राज्यों ने संसद द्वारा पारित लोकायुक्त कानून के मजमून को अपनाने के बजाय अपनी सुविधानुसार कानून बना दिये। उत्तराखण्ड जैसे राज्य में संसद द्वारा पारित मजमून के अनुसार बने कानून को नहीं माना जा रहा है और अपना अलग कानून बनाने का तर्क देकर मौजूदा कानून के अनुसार लोकायुक्त का गठन नहीं किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद लोकायुक्त का गठन करने के बजाय राज्य सरकार समान नागरिक सहिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जबकि केन्द्र सरकार स्वयं समान नागरिक सहिता बनाने जा रही है। अगर केन्द्र का कानून बनता है तो अनुच्छेद 254-के अनुसार उत्तराखण्ड के कानून का अस्तित्व नहीं रह जाता है।

शासन प्रशासन में सुचिता और सुशासन के लिये एक सशक्त भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की वकालत सन् 1960 के दशक से शुरू हो गयी थी। इस तरह की एक संस्था कल्पना सबसे पहले 1963 में विख्यात न्यायविद डा० एल.एम. सिंच्छी ने की थी। सन् 1967 में मोराजी देसाई प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 1968 में लोकपाल विधेयक संसद में पेश हआ जो पारित नहीं हआ।

पश हुआ जा पारत नहा हुआ  
लोकपाल विधेयक 2001 में भी संसद में  
पेश किया गया था लेकिन बाद में वापस ले  
लिया गया। तीसरा लोकपाल विधेयक  
2011 में संसद में पेश किया गया था। इसके  
विधेयक पर महत्वपूर्ण बहस और चर्चा हुई  
लेकिन पारित नहीं किया जा सका।  
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम,  
2013, विधेयक का अंतिम संस्करण था  
जो अंततः कानून बन गया। संसद द्वारा  
पारित इस विधेयक को 1 जनवरी 2014  
को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।  
केन्द्र में लोकपाल-लोकायुक्त कानून आने  
के बाद उड़ीसा पहला राज्य था जहां 14  
फरवरी 2014 को संसद द्वारा पारित कानून  
के मुताबिक लोकायुक्त कानून बना था और  
उसके बाद उत्तराखण्ड दूसरा राज्य था  
जिसका लोकायुक्त कानून 26 फरवरी  
2014 को अस्तित्व में आया था।

लेकिन इन्हे साल बाद भी उसका कानून के अनुसार उत्तराखण्ड को एक अद्द लोकायुक्त नहीं मिल सका। सन् 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा कानून को नकार कर 100 दिन के अंदर एक नया मजबूत लोकायुक्त कानून लाने के साथ ही लोकायुक्त के गठन का वायदा किया गया था लेकिन न तो नया कानून आया और न ही सौ दिन के बजाय 6 साल गुजरने पर भी नया लोकायुक्त अस्तित्व में आया। ऐसी ही मिलती ज़लती रामकथा अन्य उन राज्यों की भी है जो कि लोकायुक्त से वर्णित हैं।

# नाकाफी है गहलोत सरकार के कोटा में प्रवासी छान्गों की आत्महत्या का मामले को रोकने के प्रयास

अशोक भाटिया

चंबल नदी के किनारे बसा राजस्थान का शहर कोटा। इस शहर ने पिछले करीब तीन दशक में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब देने वाले नौजवानों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां खाएँ और ठाए़ल के एंट्रेस की तैयारी कराने वाले दर्जनों कोचिंग संस्थान हैं। एक तरह से शिक्षा की मंडी नजर आता है कोटा लेकिन, अब यह शहर अक्सर चर्चा में रहता है अपने ख्वाबों के बोझ तले दबकर मौत को गले लगाने वाले नौजवानों के चलते। सैकड़ों अभागे मां-बाप भी हैं, जो बढ़े अरमान लेकर अपने बच्चों को इस सपनों की नगरी में भेजते हैं लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उनकी अर्थी लेकर जानी पड़ती है। पिछले दो महीने की बात करें, तो कोचिंग हब कोटा, सुसाइड हब बना नजर आता है। इस दौरान 9 बच्चों ने खुदकुशी की है। इनमें से पांच बच्चे एक ही कोचिंग संस्थान के हैं। अभी यह साल आधा ही बीता है और इस दौरान कोटा में कुल 14 बच्चे मौत को गले लगा चुके हैं। कोटा में देश भर से करीब पैने तीन लाख बच्चे खाएँ, ठाए़ल और एम्स के एंट्रेस एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। आसान शब्दों में कहें, तो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था इन्हीं बच्चों पर टिकी है। कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री लगभग ढाई दशक पुरानी है। किसी समय में कोटा बढ़े कल-कारखानों और धुआं निकालती फैक्ट्रियों की चिमनियों के लिए जाना जाता था मगर जब इन कारखानों में मंदी आई और मशीनें बेजान हो गई तो कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार बढ़ा। अब कोटा में कोचिंग संस्थानों की बहार है। राजस्थान सरकार का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर गैर करते हुए अब करन आर राकन के लिए राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2023<sup>1</sup> पेश किया जायेगा। इस विधेयक से पहले 2018 में राजस्थान सरकार ने कोटा में कोचिंग संस्थानों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये थे लेकिन उनका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और घटनायें बढ़ती रही थीं। इसलिए अब विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) 2023 विधेयक विधानसभा से पास होकर कानून बन गया तो इसके तहत कोचिंग संस्थानों को कई अनिवार्य दिशानिर्देश दिये जा सकते हैं। विधेयक के कानून बनने पर सुनिश्चित किया जायेगा कि कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेने वाले छात्रों को योग्यता परीक्षा देनी होगी। यदि कोई उस परीक्षा को पास नहीं करता तो वह स्नातक इंजीनियरिंग या मेडिकल पाठ्यक्रमों की कोचिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। यह कानून कोचिंग संस्थानों से टॉपस का महिमांडन बंद करने का आग्रह करेगा क्योंकि यह औसत और औसत से नीचे के छात्रों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। चूंकि संस्थान साप्ताहिक रूप से नियमित परीक्षण लेते हैं, इसलिए प्रत्येक परीक्षण के बाद छात्रों के लिए एक परामर्श सत्र देना होगा। साथ ही यदि यह कानून राजस्थान सरकार द्वारा पारित हो जाता है, तो सरकार एक ई-शिकायत पोर्टल बनाएगी, जो कोचिंग सेंटरों और छात्रावासों के बारे में छात्रों और उनके अधिभावकों की शिकायतों को तुरंत सुनने और उसका निदान करने के लिए एक भीड़िप्रटर की तरह काम करेगा। पढ़ने सुनने में यह प्रयास अच्छे लगते हैं पर ये कब गैरतलब है कि जनवरी 2023 में विधायक पानाचंद मेघवाल के एक सवाल के जवाब में राजस्थान सरकार ने सदन में बताया कि बीते 4 सालों (2019-22) में कोटा में 52 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। जिसमें से साल 2022 में सर्वाधिक 25 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। इनमें 15 कोचिंग छात्र, 2 स्कूल व 8 कलेज छात्र शामिल थे। इन 15 कोचिंग छात्रों में 4 बिहार और 3 छत्तीसगढ़ के थे। बीते एक साल का यह आंकड़ा चिंताजनक था। ईंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में साल 2023 के मई और जून महीने में 9 युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। जबकि जनवरी से लेकर जून महीने तक में आत्महत्याओं की संख्या 16 पहुंच गयी है। छात्र हर साल 5 लाख तक खर्च करते हैं। ईंडिया टूडे के अनुसार कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात औसतन 125 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक है जबकि कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की लागत 1.5 लाख से ?5 लाख प्रति वर्ष आती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक हर साल इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जईई) और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रतासह-प्रवेश परीक्षा (एनईटी) जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालाना 2 लाख से भी ज्यादा छात्र कोटा जाते हैं। जबकि इन छात्रों के कारण यहां के कोचिंग संस्थाओं का कारोबार ?6,000 करोड़ का हो गया है। आत्महत्या के कारण? जनवरी 2023 में विधायक पानाचंद मेघवाल ने कोटा आत्महत्या के कारणों पर सवाल किया था, तब राजस्थान अलग-अलग कारण बताया था। सरकार न स्वीकार किया था कि आत्महत्या का कारण इंटरनल एसेसमेंट, लब अफेयर, ब्लैकमेलिंग और माता-पिता की अधिक महत्वाकांक्षा थी। 15 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले 22 वर्षीय रंजीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के पास सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि मैं बिष्णु का अंश हूं, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। 26 अप्रैल 2023 को जवाहर नगर थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रही 19 वर्षीय एक छात्रा राशि जैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा डीएसपी अमर सिंह ने इस घटना पर मीडिया को बताया कि मृतका के आत्महत्या के कारण फिलहाल सामने नहीं आये हैं। लेकिन, वह होस्टल में ही रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। अक्सर बीमार रहने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पारी थी। परीक्षाएं नजदीकी थीं और कोर्स पूरा नहीं हो हुआ, इसलिए वह तनाव में थी। जानकारी के मुताबिक, राशि अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थीं। उसके पिता किसान हैं। 24 मई 2023 को नांदा के रहने वाले 16 वर्षीय आर्यन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 12वीं का छात्र था और नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस को उसके रूम से कुछ नोट्स मिले थे, जिनमें कुछ जगहों पर किसी लड़की का जिक्र किया गया था। 12 मई 2023 को पटना के रहने वाले 17 वर्षीय नवलेश ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था कि सॉरी पापा, मेरी पढ़ाई के लिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया।

लागू होंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है।

गैरतलब है कि जनवरी 2023 में विधायक पानाचंद मेघवाल के एक सवाल के जवाब में राजस्थान सरकार ने सदन में बताया कि बीते 4 सालों (2019-22) में कोटा में 52 स्कूल-टेंट्स ने आत्महत्या की थी। जिसमें से साल 2022 में सर्वाधिक 25 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। इनमें 15 कोचिंग छात्र, 2 स्कूल व 8 कॉलेज छात्र शामिल थे। इन 15 कोचिंग छात्रों में 4 बिहार और 3 छत्तीसगढ़ के थे। बीते एक साल का यह आंकड़ा चिंताजनक था। इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में साल 2023 के मई और जन महीने में 9 युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। जबकि जनवरी से लेकर जून महीने तक में आत्महत्याओं की संख्या 16 पहुंच गयी है। छात्र हर साल 5 लाख तक खर्च करते हैं। इंडिया टूडे के अनुसार कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात औसतन 125 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक है। जबकि कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की लागत 1.5 लाख से ?5 लाख प्रति वर्ष आती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक हर साल इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेर्झी) और मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालाना 2 लाख से भी ज्यादा छात्र कोटा जाते हैं। जबकि इन छात्रों के कारण यहां के कोचिंग संस्थाओं का कारोबार ?6,000 करोड़ का हो गया है। आत्महत्या के कारण? जनवरी 2023 में विधायक पानाचंद मेघवाल ने कोटा आत्महत्या के कारणों पर सवाल किया था, तब राजस्थान सरकार ने इन आत्महत्याओं के पीछे अलग-अलग कारण बताये थे। सरकार ने स्वीकार किया था कि आत्महत्या का कारण इंटरनल एसेसमेंट, लव अफेयर, ब्लैकमेलिंग और माता-पिता की अधिक महत्वाकांक्षा थी। 15 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले 22 वर्षीय रंजीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के पास सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि मैं विष्णु का अंश हूं, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। 26 अप्रैल 2023 को जवाहर नगर थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रही 19 वर्षीय एक छात्रा राशि जैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा डीएसपी अमर सिंह ने इस घटना पर मीडिया को बताया कि मृतकों के आत्महत्या के कारण फिलहाल सामने नहीं आये हैं। लेकिन, वह होस्टल में ही रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। अक्सर बीमार रहने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाए रही थी। परीक्षाएं नजदीक थीं और कोर्स पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए वह तनाव में थी। जानकारी के मुताबिक, राशि अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। उसके पिता किसान हैं। 24 मई 2023 को नालंदा के रहने वाले 16 वर्षीय आर्यन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 12वीं का छात्र था और नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस को उसके रूम से कुछ नोट्स मिले थे, जिनमें कुछ जगहों पर किसी लड़की का जिक्र किया गया था। 12 मई 2023 को पटना के रहने वाले 17 वर्षीय नवलेश ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था कि सौरी पापा, मेरी पढ़ाई के लिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया।

## जल-आपातकाल : उठावे में उलट रहा

उपेन्द्र शंकर

उरुग्वे पिछले साढ़े तीन साल से सदी के सबसे बुरे सूखे से ज़्यादा रहा है। उरुग्वे में बारिश आमतौर पर सर्दियों में ठंडी हवाओं और गर्मियों में बार-बार आने वाले तूफानों का परिणाम होती है, पर इस गर्मी (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023) में बहुत कम बारिश हुई। 'राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान' द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गर्मी के दौरान औसत वर्षा 126.4 मिमी थी जो औसत वर्षा से 225.4 मिमी कम थी। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में स्थित देश उरुग्वे के राष्ट्रपति लुइस लैकले पोउ ने पिछले तीन साल, खासकर सात महीने के भीषण सूखे के बाद अभी 19 जून को राजधानी मोटेरीटियो और मदान-मरीया थेसे में पाना का आपूर्त करने वाल विभाग को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। यह सब तब हुआ जबकि उरुग्वे दुनिया के सबसे स्वच्छ, सबसे प्रचुर जलस्रोतों वाले देशों में से एक है। वर्ष 2004 में उरुग्वे ने पानी को निजीकरण से बचाने के लिए सर्विधान में संशोधन किया था और देश में पानी एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में चिह्नित किया गया था।

पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति लैकले पोउ ने बताया कि स्थिति को सुधारने और राजधानी के लिए पीने के पानी का एक नया स्रोत प्रदान करने के लिए सैन-जोस नदी पर एक जलाशय के निर्माण की घोषणा की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जलाशय और उपरके पाइपलाइन्स

# चित्रकूट - उन्नाव संदेश

## 35 क्षार्टर शराब समेत एक दबोचा

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृद्धा शुक्ला के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम को जारी अधियान में प्रभारी निरीक्षक सरधुआ दीपेन्द्र सिंह की अगुवाई में दरोगा दिवेश कुमार पांडेय की टीम ने बच्चा सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी बांध धुमाई सुर्की के कब्जे से 35 क्षार्टर शराब समेत गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ थाने में आबकारी अधियानम के तहत मामला दर्ज किया। टीम में दरोगा दिवेश कुमार पांडेय, सिंपाही महेंद्र, वर्धन्द शामिल रहे।

## राजापुर पुलिस ने चार को दबोचा

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृद्धा शुक्ला के निर्देश पर वांछित/वारंटरी की गिरफ्तारी को जारी अधियान में प्रभारी निरीक्षक राजापुर भारतीय मिश्न की अगुवाई में वरिष्ठ दरोगा रामवीर सिंह की टीम ने वांछित विरंजन दीपेन्द्र सिंह में सर्वोत्तम उर्फ मुरती उर्फ बाबूलाल पुत्राणा नशु, रामपिलान उर्फ अतिर उत्तर पुत्र गोविन्द, मुलीधर उर्फ बाबूलाल पुत्राणा नशु, रामपिलान उर्फ अतिर उत्तर पुत्र गोविन्द निवासी सरायं तलेया कक्षा राजापुर को गिरफ्तार किया। टीम में वरिष्ठ दरोगा रामवीर सिंह, सिंपाही उमेन्द्र प्रियांती शामिल रहे।

## धान खरीद को करायें पंजीकरण

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिला खाद्य विधान अधिकारी ने बताया कि धान खरीद 2023-24 के तहत सरकारी धान खरीद केन्द्रों पर सीधे किसानों से एक नवम्बर से धान खरीद होगी। सरकारी धान खरीद केन्द्रों पर धान बेचने को किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है।

शनिवार को उन्होंने बताया कि धान खरीद को पंजीकरण एक जुलाई से 31 अगस्त तक होगा। धान बिक्री को पंजीकरण करने को खाद्य विभाग की बेकासी अथवा विभाग के मोबाइल एप जाकर पंजीकरण करना होगा। जिला किसानों ने पिछले वर्षों में धान गेहू़ खरीद पंजीकरण कराया था, उन्हें नवान पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पुराने पंजीकरण से सूचनाओं को संरेखित करना होगा। धान बिक्री को पंजीकरण व्यवस्था औटोपी आधारित है।

## पक्षकारों को दिलाये पैंतीस लाख

### 40 हजार रुपये

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। अपर जिला जज/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उपर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर शनिवार को मोटर दुर्घटना प्रतिकर वारा मामलों के निस्तारण बाबत विशेष लोक अदालत पीठासीन अधिकारी दिवेश चन्द्र ने लगाई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की अध्यक्षता में हुई। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 24 वार्डों का निस्तारण कर प्रतिकर पैंतीस लाख चालीस हजार रुपये पक्षकारों को दिलाये।

## डीएम ने देखा पहाड़ी-बिसंडा सड़क मार्ग



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिलाधिकारी अधिकारी अनन्द ने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के नियमान्वयन पहाड़ी-बिसंडा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। उन्हें सहायक अधियांता ने बताया कि पहाड़ी-बिसंडा मार्ग 30 किमी का निर्माण हो रहा है।

शनिवार को जिलाधिकारी को सहायक अधियांता ने बताया कि बांध नदी के पास पांच सौ मीटर सड़क का कार्य शेष है। पहाड़ी-नांदी की तरफ चार किमी सड़क पर यात्रा की जाने की अपीली रही। सड़क की शिक्केनेस एवं गुणवत्ता की खुदाई कराने की जाने की अपीली रही। सड़क की शिक्केनेस एवं गुणवत्ता सही मिली। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयों को निर्देश दिए कि जो कार्य शेष हैं, तत्काल शासन की मंशानुसार समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण करायें। इसी मीठे पर डीमी निर्माण विभाग प्रांतीय खंड समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

## डीएम के निर्देश पर सूचना अधिकारी कार्यालय परिसर की हुई सफाई



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अधियान के तहत जिला सूचना कार्यालय परिसर में साफ-सफाई कराई गई।

शनिवार को जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में नगर पालिका पर्षद कर्वी के सफाई नायक दुलीचंद ने पालिका के सफाई कर्मियों से पूरे परिसर की साफ-सफाई, झाड़-झाड़ियाँ कटवाकर जलभराव समाप्त कराया। उल्लेखनीय है कि यहां पर नगर पालिका शहर में हुए अतिक्रमण का मलबा फेकता था। इससे सूचना अधिकारी कार्यालय परिसर में चैत्रपाक गन्धी फैली थी।

पिछले दिन जिलाधिकारी अधिकारी अनन्द ने पुस्तकालय बवन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण दौरान उन्होंने यहां फैली गन्दी देखी थी। गन्धी देखकर जिलाधिकारी ने तत्काल साफ-सफाई के निर्देश दीजै नगर पालिका को दिये थे। उनके निर्देश पर सूचना अधिकारी कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की गई।

# पार्टी से सर्वोपरि नहीं है कोई: अनिल प्रधान सपा की हुई मासिक बैठक

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। समाजवादी पार्टी के जिलाधिकारी की रोकथाम को जारी अधियान में प्रभारी निरीक्षक सरधुआ दीपेन्द्र सिंह की अगुवाई में दरोगा दिवेश कुमार पांडेय की टीम ने बच्चा सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी बांध धुमाई सुर्की के कब्जे से 35 क्षार्टर शराब समेत गिरफ्तार किया। टीम में दरोगा दिवेश कुमार पांडेय, सिंपाही महेंद्र, वर्धन्द शामिल रहे।

शनिवार को सपा जिला कार्यालय पर चारों वर्ष संसद बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं में नायं पंचायत वार सम्मेलन बुलाकर बूजु कमेटीयों को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में कहा कि जिला कार्यालय में सभी का सम्मान है और होता रहेगा। पूर्व पटेल व सदर विधायक अनिल प्रधान के मुख्य आविष्य में हुई।

बैठक में मतदाता पुनरीक्षण कार्य एवं

कहा कि वे कार्यकारी और हर स्तर पर मदद करें। कोई भी अधिकारी या कमर्चारी परेशन करते तो उन्हें बतायें। सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि सपा मुख्य अधिकारी या बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं में नायं पंचायत वार सम्मेलन बुलाकर बूजु कमेटीयों को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में सभी का सम्मान है और होता रहेगा। पूर्व पटेल व सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि वे कार्यकारी और हर स्तर पर मदद करें। कोई भी अधिकारी या कमर्चारी परेशन करते तो उन्हें बतायें। सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि सपा मुख्य अधिकारी या बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं में नायं पंचायत वार सम्मेलन बुलाकर बूजु कमेटीयों को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में सभी का सम्मान है और होता रहेगा। पूर्व पटेल व सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि वे कार्यकारी और हर स्तर पर मदद करें। कोई भी अधिकारी या कमर्चारी परेशन करते तो उन्हें बतायें। सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि सपा मुख्य अधिकारी या बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं में नायं पंचायत वार सम्मेलन बुलाकर बूजु कमेटीयों को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में सभी का सम्मान है और होता रहेगा। पूर्व पटेल व सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि वे कार्यकारी और हर स्तर पर मदद करें। कोई भी अधिकारी या कमर्चारी परेशन करते तो उन्हें बतायें। सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि सपा मुख्य अधिकारी या बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं में नायं पंचायत वार सम्मेलन बुलाकर बूजु कमेटीयों को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में सभी का सम्मान है और होता रहेगा। पूर्व पटेल व सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि वे कार्यकारी और हर स्तर पर मदद करें। कोई भी अधिकारी या कमर्चारी परेशन करते तो उन्हें बतायें। सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि सपा मुख्य अधिकारी या बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं में नायं पंचायत वार सम्मेलन बुलाकर बूजु कमेटीयों को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में सभी का सम्मान है और होता रहेगा। पूर्व पटेल व सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि वे कार्यकारी और हर स्तर पर मदद करें। कोई भी अधिकारी या कमर्चारी परेशन करते तो उन्हें बतायें। सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि सपा मुख्य अधिकारी या बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं में नायं पंचायत वार सम्मेलन बुलाकर बूजु कमेटीयों को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पहली बैठक में सभी का सम्मान है और होता रहेगा। पूर्व पटेल व सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि वे कार्यकारी और हर स्तर पर मदद करें। कोई भी अधिकारी या कमर्चारी परेशन करते तो उन्हें बतायें। सदर विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि सपा मुख्य अधिकारी या बैठक में हुई।

जिले की दोनों विधानसभाओं म

